

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (i) यह अधिनियम 'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017' कहलाएगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) का प्रतिस्थापन

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा घरेलु एवं गैर-घरेलु (व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ की जानेवाली जलापूर्ति के लिए उस दर से भुगतान किया जाएगा, जो नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

परन्तु यह दर, जहां तक व्यवहार्य हो, जल संकर्म (वाटर वर्क्स) संबंधी प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्यहास तथा ऋण शोधन एवं अन्य प्रभार, वितरण लागत, वितरण-हानि, यदि कोई हो, सहित, सभी आच्छादित होंगे।”

यह विधेयक झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 12 अगस्त, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 12 अगस्त, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष